

	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)		
	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,		
सत्यमेव जयते	वस्तु एवं सेवा कर भवन	GST Building, 7 th Floor, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015	
	सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास,		
	आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015		
 : 079-26305065		टेलिफैक्स : 079 - 26305136	

7452 / 07456

क फाइल संख्या : File No : **V2/131/GNR/2018-19**

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-120-18-19**

दिनांक Date : **20-11-2018** जारी करने की तारीख Date of Issue: **6/12/2018**

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

C. file

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश :
48/Ref/AC/Stax-2018-19 दिनांक : **20-07-2018** से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **48/Ref/AC/Stax-2018-19**, Date: **20-07-2018** Issued by:
Assistant Commissioner, CGST, Div: Palanpur, Gandhinagar Commissionerate,
Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Kindle Engineering

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

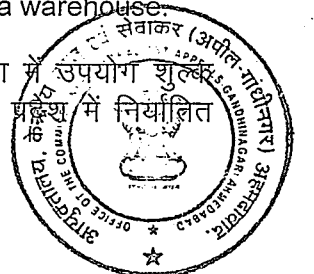
(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।



(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

... 2...

- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (C) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

घ अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- एबी/35-इ के अंतर्गत:-

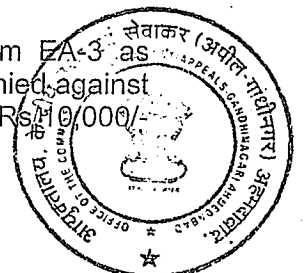
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। गढ़ ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/-



where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any

---2A---

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 34 के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल हैं

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

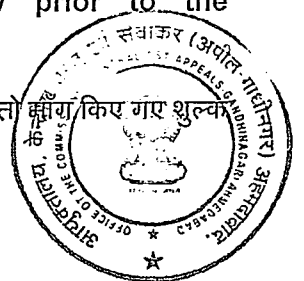
For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो कौन सा शुल्क माँगा जाएगा/किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Kindle Engineering & Construction Pvt. Ltd., Survey No.44,67,68,68a,89,89a and 111, At Village Charanka, Taluka Santalpur, Distt. Patan, Gujarat-385 350 (in short 'appellant') against Order-in-Original No.48/Ref/AC/S.Tax-2018-19 dated 20.07.2018 (in short 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-Palanpur (in short 'adjudicating authority').

2. Briefly stated that the adjudicating authority vide impugned order in denovo adjudication rejected refund claim of interest Rs.45,96,441/- paid on service tax paid to the govt. undertaking which was exempted retrospectively vide Section 104 of the Finance Act, 1994.

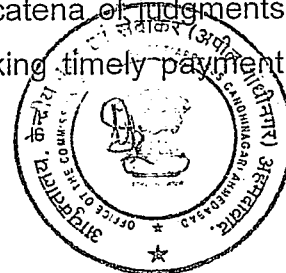
3. Aggrieved with the impugned letter, the appellant filed the present appeal wherein, *inter alia*, submitted that –

- The adjudicating authority has erred in holding that there is no provision for refund of interest on service tax paid under Notifn. No.41/2016-ST dated 22.09.2016. This notifn is prospective one and is applicable to the taxable service provided or to be provided w.e.f. the date of its publication in the official gazette and not applicable in the present case.
- It is a trait law that interest liability always goes in hand with tax liability. In the present case, as provided under sub-section (2) of Section 104 of the Act, by creating deeming fiction, no tax liability incurred, hence question of belated payment of tax is not the case.
- The adjudicating authority failed to observe that Hon'ble Commissioner(Appeals) vide order dtd.18.04.2018 specifically allowed the appeal with consequential relief to the appellant but took shelter that no order is passed for payment of interest.

4. Personal hearing in the matter was held on 25.10.2018. Shri Jatin Mehta, Authorized Representative, appeared before me on behalf of the appellant and reiterated the grounds of appeal; pointed out para 7 of the OIO to show that AC has whimsically denied interest and submitted citation for interest.

5. I have carefully gone through the appeal memorandums, submissions made at the time of personal hearing and evidences available on records. I find that the main issue to be decided is whether the appellant is entitled to refund of interest paid on belated payment of service tax paid or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.

6. Prima facie, I find that this is a remand case wherein the adjudicating authority was directed to give consequential relief to the appellant vide OIA No.AHM-EXCUS-003-APP-0277-17-18 dated 27.03.2018 passed by the undersigned. I find that the adjudicating authority has failed to understand the meaning of 'consequential relief' in quasi-judicial proceedings. When 'consequential relief' is ordered, it amounts to grant all benefits accrued under the law. I find that it has been held in catena of judgments of higher appellate forum that interest is levied for default in making timely payment of



duty. Had it been paid well in time as per law, there would be no question of payment of interest on belated payment because delayed payment of duty itself attract the payment of interest which is inextricably associated with duty. Hence, when duty is exempted retrospectively, interest paid on it for belated payment is also exempted. I find that Section 11B of the Central Excise Act, 1944, as made applicable to Section 83 of the Finance Act, 1994, clearly provides for refund of duty and interest, if any, paid on such duty. So, the findings of the adjudicating authority that Notifn No.41/2016-ST dated 22.09.2016 does not provide for refund of interest paid on duty is totally mis-placed. I find that in case of CCE, Delhi-III Vs. Northern Minerals Ltd. reported in 2007(216) ELT-198 (P&H), the Hon'ble High Court has held as under:

"Refund of interest - Excess amount of interest paid by assessee under Section 11AB of Central Excise Act, 1944 - Payment of interest cannot be excluded from provisions of Section 11B ibid merely because it uses the expression 'refund of duty' because delayed payment of duty itself attract the payment of interest which is inextricably associated with duty - Moreover, such a collection of interest on account of delayed payment of duty would be unauthorized imposition of tax which is impermissible by provisions of Article 265 of Constitution of India [para 11]"

Similar view is taken by the Hon'ble CESTAT, Bangalore in case of CM EnviroSystems Pvt. Ltd. Vs.CCE, Bangalore, wherein it is held that:

"Refund - Interest for delayed payment of duty - Paid at rate of 2% and also Rs. 1000 per day, as per Rule 8(3) of Central Excise Rules, 2002 - In view of Rule ibid, being held ultra vires in Lucid Colloids Ltd. [2006 (200) E.L.T. 377 (Raj.)], assessee found entitled to refund of excess of 2% - Its rejection on ground that there was no provision for refund of interest, held to be unjustified - Section 11B of Central Excise Act, 1944. [para 5]"

Accordingly, the appeal filed by the appellant is allowed subject to provisions of section 11B of the Central Excise Act, 1944.

7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

Attested:

B.A. Patel
25/12/18

(B.A. Patel)
Supdt.(Appeals)
Central Tax, Ahmedabad.

BY SPEED POST TO:

M/s. Kindle Engineering & Construction Pvt. Ltd.,
Survey No.44,67,68,68a,89,89a and 111,
At Village Charanka, Taluka Santalpur,
Distt. Patan, Gujarat-385 350.

उमा शंकर

(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)



Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone.
- (2) The Commissioner, CGST, Gandhinagar (RRA Section).
- (3) The Asstt. Commissioner, CGST , Division- Palanpur.
- (4) The Asstt. Commissioner(System), CGST, Gandhinagar
(for uploading OIA on website)
- ~~(5)~~ Guard file
- (6) P.A. file.